मो. को मकबूल दमनू

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य

5 जनवरी, 1972

[एसएम सीकरी, सीजे, एसएम सीकरी, सीजे, जे.एम शेलाट, आईडी दुआ, एच.आर. खन्ना, जी.के. मित्तर]

जम्मू और कश्मीर का संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1965- सदर-ए- के स्थान पर गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान रियासत के स्पष्टीकरण की दृष्टि से संशोधन की वैधता भारत के संविधान के अनुच्छेद 370(1) का आज भी उल्लेख है राज्य के प्रमुख के रूप में सदर-ए-रियासत-- राज्यपाल की सहमति जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम,1967 क्या वैध कानून- कला में संशोधन का परिणाम है। 367 का भारत का संविधान इस आशय का है कि सदर का संदर्भ- आई-रियासत को राज्यपाल के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा चाहे वह अनुच्छेद में संशोधन के बराबर है। 370(1) पिछले दरवाजे से—निरोध अधिनियम की धारा 8(1) सामने आती है या नहीं अत्यधिक प्रत्यायोजन- परंतु बुरा है क्योंकि यह विरोधाभासी है जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 103 के साथ क्या हिरासत आदेश कला का उल्लंघन करता है। 21 और 22 की संविधान-क्या नजरबंदी बुरी है क्योंकि नजरबंद करना

प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया था कि क्या आदेश दिया गया है कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया और निष्पादित किया गया।

मूल रूप से अनुच्छेद 37 यू(1) के स्पष्टीकरण के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार को अधिनियमित किया गया इसका मतलब उस व्यक्ति से है जिसे कुछ समय के लिए पहचाना जा रहा है भारत के राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में अभिनय कर रहे हैं अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर, 1952 में राज्य की संविधान सभा ने निर्णय लिया कि महाराजा नामित राज्य के निर्वाचित प्रमुख द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा सदर-ए-रियासत के रूप में परिणामी परिवर्तन किये गये भारत के संविधान के अनुच्छेद 370(i) और में राज्य की सरकार के अनुच्छेद का स्पष्टीकरण जम्मू और कश्मीर को व्यक्ति के अर्थ में परिभाषित किया गया था समय जम्मू के सदर-ए-रियासत के रूप में पहचाना जाता है और कश्मीर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर के संविधान द्वारा (छठा संशोधन अधिनियम) 1965 जिसे सदर-ए-रियासत की सहमति प्राप्त हुई जम्मू और कश्मीर के संविधान ने इसके लिए प्रावधान किया सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति। नहीं कला में परिणामी परिवर्तन किया गया। 370(1) की भारत का संविधान, लेकिन अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया प्रभाव जो जम्मू के सदर-ए-रियासत का संदर्भ देता है कश्मीर को

राज्यपाल के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जम्मू-कश्मीर और वहां की सरकार का संदर्भ उक्त राज्य को संदर्भ सहित समझा जाएगा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल उनकी सलाह पर काम कर रहे हैं मंत्री परिषद् जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 8) के बाद विधान सभा द्वारा पारित कर स्वीकृति प्राप्त की गई जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की. याचिकाकर्ता था के आदेश से इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया

जिला मजिस्ट्रेट दिनांक 24 जून 1970 एक रिट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका याचिकाकर्ता तर्क दिया

(i) कि जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1967 अमान्य था क्योंकि यह था ही नहीं केवल सदर-ए-रियासत द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी जिसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 370(1) की व्याख्या में राज्य के प्रमुख के रूप में; (ii) उपधारा में कार्रवाई 4(2) द्वारा जोड़ा गया परंतुक (1) निरोध अधिनियम की धारा 8 खराब थी क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल से पीड़ित: (iii) जो वहां था संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन किया गया है; (iv) किसी भी तारीख में परंतुक खराब था क्योंकि यह जम्मू के संविधान की धारा 103 के तहत दोषी ठहराया गया और कश्मीर; (v) कि 1015 हिरासत में लेने का आदेश ख़राब था क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास था अपना

दिमाग नहीं लगाया; और (vi) कि हिरासत का आदेश ख़राब था क्योंकि इसे उसके अनुसार परोसा या क्रियान्वित नहीं किया गया था कानून के साथ.आयोजित:

अभीनिर्धारित:(i) (ए) अनुच्छेद 370 उप की आवश्यक विशेषता-खंड (1) (बी) और (डी) की सहमति आवश्यक है राज्य सरकार या राज्य का परामर्श सरकार। राज्य सरकार विशेष तौर पर क्या कर रही है समय का निर्धारण संविधान के अनुरूप होना चाहिएजम्मू और कश्मीर के. स्पष्टीकरण ने इससे अधिक कुछ नहीं किया उस पर विद्यमान संवैधानिक प्रावधान को वैसे ही पहचानें दिनांक और स्पष्टीकरण 17 नवंबर से प्रतिस्थापित, 1952 को भी संवैधानिक मान्यता से अधिक कुछ नहीं मिला राज्य में प्रावधान. इसलिए कोई कठिनाई नहीं है यह मानते हुए कि अनुच्छेद 370(1)(बी) और अनुच्छेद 370(1)(डी) के निर्धारण और संशोधन पर कोई सीमा न रखें जम्मू और कश्मीर का संविधान. यदि कोई सीमा है इसे राज्य के संविधान में पाया जाना चाहिए। अनुभाग जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 147 स्वयं प्रावधान करती है कि उस धारा के अंतर्गत भारतीय संविधान नहीं हो सकता संशोधित. [1025 एफजी](बी) कला की व्याख्या। 370(1) का संचालन बंद हो गया था क्योंकि अब जम्मू का कोई सदर-ए-रियासत नहीं रहा कश्मीर। यदि परिभाषा स्पष्टीकरण में निहित है 'राज्य की सरकार' शब्दों पर लागू नहीं हो सकता अनुच्छेद 367(4) में दिये गये अर्थ को यथा

संशोधित करना होगा इसे दिया गया. यदि यह अर्थ दिया जाय तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल सहमति देने के लिए सक्षम हैं, अनुच्छेद 370 में निर्धारित और अन्य कार्य करना जम्मू और कश्मीर संविधान द्वारा नीचे. [1026 ई.पू.]

संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, [1969] 2 एससीआर 365; करने के लिए भेजा।

(सी)विवाद यह है कि संविधान की धारा 147 जम्मू-कश्मीर सदर के स्थायी अस्तित्व पर विचार कर रहा है- i-रियासत क्योंकि यह धारा स्पष्ट रूप से विधानसभा पर रोक लगाती है कला के किसी भी प्रावधान में संशोधन से। 147 और एकइस खंड में जारी प्रावधान यह है कि सहमति संविधान में संशोधन द्वारा दिया जाना चाहिए सदरी-रियासत, स्वीकार नहीं किया जा सकता. संविधान ही इसमें धारा 18 शामिल है जो यह प्रदान करती है जब तक कि संदर्भ न हो अन्यथा सामान्य खण्ड अधिनियम, संवत 1977 की आवश्यकता है इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा यह राज्य के अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है विधान मंडल। इस अधिनियम के आधार पर राज्यपाल है सदर-ए-रियासत का उत्तराधिकारी। वह इसका हकदार होगा सदर-ए-रियासत की सभी शक्तियों का प्रयोग करें। कोई नहीं है संदेह है कि वह उत्तराधिकारी है। से यह बिल्कुल स्पष्ट है जम्मू-कश्मीर की धारा 26, 27 और 28 संविधान वास्तव

में सदर-ए-रियासत नाम है राज्य के मुखिया को दिया गया. उक्त संविधान के तहत संशोधन के अनुसार राज्य के प्रमुख को राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है-न ही संशोधित धारा 26 की उपधारा (2) निहित हैउसमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल नहीं हैंसदर-इरियासत के रूप में चुना गया था, लेकिन का तरीका नियुक्ति से वह किसी भी तरह का उत्तराधिकारी नहीं बन पायेगा सदर-ए-रियासत. दोनों राज्य के मुखिया हैं. [1026 डी-1027 सी] (डी) गोलकनाथ के मामले में निर्धारित नियम लागू नहीं था वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए. ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को विधायिका के प्रति गैरजिम्मेदार बना दिया गया है एक जिम्मेदार सरकार के रूप में इसका मौलिक चरित्र हैपरिवर्तित. जैसे मुखिया के पदनाम में बदलाव सरकार पहले परिचय द्वारा लाई गई थी सदर-ए-रियासत के कार्यालय में भी परिवर्तन किया गया है सदर इ-री से उनके डिजाइन, राष्ट्र में लाया गया राज्यपाल को असत. 'तर्क से चटाई की आवश्यकता थी राज्यपाल को प्रतिस्थापित कर दिया गया है1016 सदर-ए-रियासत के स्थान पर। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है उस सरकार के चरित्र में एक से एक होना परिवर्तन लोकतांत्रिक से गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था। [1027 जी-1028 बी]गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, [1967] 2 एससीआर 762; विशिष्ट। (ई) अनुच्छेद 367(4) के खंड (एए) और (बी) प्रतिस्थापित 1965 के सीओ 74 द्वारा (जम्मू के लिए संविधान लागू)।और कश्मीर) द्वितीय संशोधन आदेश, 1965 के बारे में नहीं कहा जा सकता अनुच्छेद 370(1) में

पिछले दरवाजे से संशोधन हो। स्पष्टीकरण निरर्थक हो गया था और सदर-ए- का संदर्भ दिया गया था। संविधान के अन्य भागों में भी रियासत बन गई थी दो विकल्प थे, पहला, या तो चले जाओ अदालतें "राज्य सरकार" शब्दों की व्याख्या करें और इसे इसका कानूनी अर्थ दें या दूसरा कानूनी अर्थ देंएक परिभाषा खंड में अर्थ. जो किया गया है वो यही है खंड (एए) और (बी) जोड़कर एक परिभाषा दी गई है जो न्यायालयों को किसी भी स्थिति में दिया जाना चाहिए। [1028 डे] तदनुसार, यह माना जाना चाहिए कि संशोधित अधिनियम वैध था राज्यपाल ने दी मंजूरी. [1028 जी]

(2) जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) कार्यवाही करना। 1967 ने कोई विधायी शक्तियाँ नहीं सौंपीं कोई। यह हिरासत में लेने पर कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता हैधारा 8 में परंतुक को सम्मिलित करके प्राधिकार निर्देश दें कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाए उससे संवाद करना जनहित के विरुद्ध होना चाहिए जिन आधारों पर हिरासत का आदेश दिया गया था। कब हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी ऐसा निर्देश देना चुनता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं वैधानिक शक्ति। [1028 एच-1029 ए]

(3) हिरासत को उल्लंघन नहीं कहा जा सकता संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 क्योंकि वे थेसंविधान के अनुच्छेद 35(सी) द्वारा बाहर रखा

गया। [1029 बी](4) आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता हो सेंट्रल जेल श्रीनगर में निरुद्ध और आदेश की एक प्रतिपुलिस उपाधीक्षक को पृष्ठांकित किया गया था निरोध अधिनियम की धारा 4 द्वारा आवश्यक। धारा 75(1) सीआरपीसी का अनुपालन किया गया था क्योंकि आदेश लिखित में था हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। धारा 76 सीआरपीसी का इस मामले में कोई आवेदन नहीं था क्योंकि यह केवल लागू होता है जब न्यायालय निर्देश देता है कि सुरक्षा ली जाए। [1029 ई.](5) यह तर्क कि धारा 8 का परंतुक डाला गया जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) द्वाराअधिनियम, 1967 जम्मू और की धारा 103 के साथ विरोधाभासी था कश्मीर संविधान को स्वीकार नहीं किया जा सका. यह बिल्कुल है स्पष्ट है कि विधायिका को सीधे संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है धारा 103 न ही इसके द्वारा अभ्यास करने की शक्ति है उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एस. 103 भ्रामक. लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि परंतुक अधिकारातीत है क्योंकि प्रावधान और अधिनियम उच्च न्यायालय या इस पर रोक नहीं लगाता है कोर्ट हिरासत की वैधता पर गौर कर रहा है। उच्च न्यायालय और यह न्यायालय प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं उचित मामले में राज्य को बुलाकर क्षेत्राधिकार हिरासत और अन्य के आधार उसके समक्ष प्रस्तुत करें स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सामग्री कि बंदी था कानून के अनुसार हिरासत में लिया जा रहा है. फ़ाइल से राज्य द्वारा उच्च

न्यायालय के समक्ष आधार प्रस्तुत किया गया किस बंदी को हिरासत में लिया गया है इसकी प्रासंगिकता दिखाई गई है राज्य की सुरक्षा के लिए और ऐसा नहीं कहा जा सकता हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने इस पर अपना दिमाग नहीं लगाया मामले के तथ्य. [1029 एफ-1030 जी] 1017 प्रेम चंद गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर यूपी, [1963] सप्ल. 1 एससीआर 885; एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य, [1950] एससीआर 8.8 का उल्लेख किया गया है।

निर्णय: मूल क्षेत्राधिकार: 1971 की रिट याचिका संख्या 144 बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ता की ओर से आरके गर्ग, एससी अग्रवाल, एके गुप्ता और आरके जैन।

जम्मू-कश्मीर राज्य के महाधिवक्ता ईश्वर सिंह बख्शी, प्रतिवादी की ओर से एमसी चागला, आरएन सच्चे और एसके ढोलकिया।

निरेन डे- भारत के अटॉर्नी-जनरल के लिए; उनके साथ अधिवक्ता आरएन सच्चे और राम पंजवानी भी थे।

न्यायालय का फैसला सीकरी, सीजे द्वारा सुनाया गया यह कला के तहत एक याचिका है। संविधान के अनुच्छेद 32 में जम्मू और कश्मीर निवारक हिरासत अधिनियम, 1964 (1964 का जम्मू एवं कश्मीर

अधिनियम XIII) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत को चुनौती दी गई है, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाएगा।

24 जून, 1970 को, बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित शर्तों में आक्षेपित हिरासत आदेश पारित किया: "कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बारामूला संख्या पीडीए/आईएमबी/81 दिनांक 24-6-1970 आदेश जबकि मैं, एसएस रिज़वी, जिला मजिस्ट्रेट, बारामुला, इस बात से संतुष्ट हैं कि मोहम्मद मकबूल दमनू पुत्र गुलाम मोही-उन-दीन दमनू उर्फ माधा जू निवासी संग्रामपोरा को राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। करना; इसलिए, अब, जम्मू और कश्मीर निवारक हिरासत अधिनियम, 1964 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एसएस रिजवी, जिला मजिस्ट्रेट, बारामूला एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि उक्त मोहम्मद मकबूल दमनू को हिरासत में लिया जाए। केंद्रीय जेल श्रीनगर में, मुख्य शर्तों के अधीन-

अनुशासन के उल्लंघन के लिए कार्यकाल, अनुशासन और सजा, जैसा कि जे एंड के डिटेनस जनरल ऑर्डर, 1968 में निर्दिष्ट किया गया है।

एसडी/-

जिला मजिस्ट्रेट, बारामूला.

क्रमांक कॉन/826-30 दिनांक 24-6-1970 प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. श्री अब्दुल माजिद लोन, उप. जम्मू-कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम, 1964 की धारा 4 द्वारा प्रदान किए गए आदेश के निष्पादन के लिए एसपी सोपोर दो प्रतियों में। आदेश की सूचना मोहम्मद मकबूल दमनू को पढ़कर दी जाएगी और एक प्रति विधिवत निष्पादित करके, इस पर वापस कर दी जाएगी। कार्यालय।

उसी तिथि को, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा के तहत एक आदेश पारित किया। 8, एस के साथ पढ़ें। अधिनियम के 13-ए में निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए कि जिस आधार पर उसकी हिरासत आधारित थी, उसका खुलासा करना सार्वजनिक हित के खिलाफ था। 11 जुलाई, 1970 को, सरकार ने हिरासत के आदेश, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, जिस आधार पर आदेश दिया गया था, और मामले से संबंधित अन्य विवरणों पर विचार करने के बाद उक्त नजरबंदी आदेश को मंजूरी दे दी।

याचिकाकर्ता ने 10 अप्रैल, 1971 को इस न्यायालय में एक आवेदन भेजकर अनुरोध किया कि उसे इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि वह अपनी हिरासत को चुनौती देने के लिए उचित रिट दायर करने में सक्षम हो सके। इस न्यायालय ने 11 मई, 1971 को निर्देश दिया कि इस आवेदन को कला के तहत रिट याचिका के रूप में माना जाए। संविधान के 32 और नियम निसी का निर्देशित मुद्दा। न्यायालय ने आगे

निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को याचिका की सुनवाई से दो दिन पहले उसके समक्ष पेश किया जाए। राज्य ने जवाब में हलफनामा दाखिल किया. याचिकाकर्ता ने 27 जुलाई, 1971 को एक वकील के माध्यम से औपचारिक रिट याचिका दायर की। राज्य ने फिर से जवाब में एक हलफनामा दायर किया। अतिरिक्त आधार जुटाने की अनुमति के लिए किए गए आवेदन पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक व्यापक संशोधित याचिका की अनुमति दी। 9 अक्टूबर 1971 को इस न्यायालय में संशोधित रिट याचिका दायर की गई। राज्य ने जवाब में एक और हलफनामा दाखिल किया.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री गर्ग ने हमारे सामने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

(1) कि जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम VIII) - जिसे इसके बाद संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया था, अमान्य था क्योंकि इसे सदर-रियासत द्वारा सहमति नहीं दी गई थी;

(2) एस द्वारा डाला गया परंतुक। 4(2) उप-एस में।

(1) एस. 8 ख़राब है क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है;

(3) कला का उल्लंघन हुआ है। 21 और कला. संविधान के 22;

(4) किसी भी दर पर, परंतुक ख़राब है क्योंकि यह एस के साथ टकराव करता है। जम्मू और कश्मीर के संविधान के 103;

(5) कि हिरासत का आदेश खराब है क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है; और (6) कि हिरासत का आदेश ख़राब है क्योंकि इसे कानून के अनुसार तामील या निष्पादित नहीं किया गया था।

अपने पहले तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने कला के तहत आग्रह किया कि। भारतीय संविधान का 370 एकमात्र प्राधिकारी है जिसे 'जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार' के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह सदर-ए-रियासत है, अनुच्छेद 370 में विचार किया गया है कि सदर-ए-रियासत जम्मू राज्य का प्रमुख होगा और कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास सदर-ए-रियासत के कार्यालय को समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। उन्होंने आगे आग्रह किया कि एस. 147 सीएफ, जम्मू और कश्मीर का संविधान यह भी मानता है कि सदर-ए-रियासत अस्तित्व में रहेगा और 'राज्य का प्रमुख होगा। उन्होंने आग्रह किया कि सदर-ए-रियासत से छुटकारा पाने का एकमात्र संभावित तरीका जम्मू और कश्मीर पर लागू भारत के संविधान में संशोधन करना होगा।

विद्वान अटॉर्नी-जनरल, जो भारत सरकार की ओर से पेश हुए, और श्री छागला, जो राज्य की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर का संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1965, जिसे सदर की सहमति प्राप्त हुई थी -ए-रियासत ने जम्मू-कश्मीर के संविधान में वैध रूप

से संशोधन किया और सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वैध रूप से प्रावधान किया, और इसलिए, राज्यपाल जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध को सहमति देने के लिए सक्षम थे (संशोधन) अधिनियम, 1967। हमारे सामने उठाए गए बिंदुओं की सराहना करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में हुए विभिन्न संवैधानिक परिवर्तनों का एक संक्षिप्त इतिहास देना आवश्यक है। एचएच

जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत के महामहिम गवर्नर-जनरल को संबोधित एक पत्र में, भारत के डोमिनियन में शामिल होने की पेशकश की। 27 अक्टूबर, 1947 को गवर्नर-जनरल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ शर्तें तय कीं जिनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। 5 मार्च, 1948 को, जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने एक जिम्मेदार सरकार बनाने की घोषणा जारी की। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद को राज्य के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर एक राष्ट्रीय सभा का गठन करने के लिए कदम उठाना था। 20 जून, 1949 को महाराजा सर हरि सिंह ने अस्थायी अवधि के लिए अपने विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्य अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपे। 25 नवंबर, 1949 को युवराज करण सिंह द्वारा एक उद्घोषणा जारी की गई थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने वाले भारत के संविधान को संविधान

सभा द्वारा अपनाया जाएगा जहां तक यह जम्मू और कश्मीर में शासन करने के लिए लागू होता है। राज्य और भारत के विचारित संघ का संबंध। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और उसी दिन कुछ प्रावधान लागू हुए और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।

संविधान का अनुच्छेद 370 भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 370 इस प्रकार है:

370. (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-

(ए) अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(बी) उक्त राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति सीमित होगी-

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे मामले, जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भारत के डोमिनियन में राज्य के विलय को नियंत्रित करने वाले विलय पत्र में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित किया जाता है। उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बना सकता है; और

(ii) उक्त सूचियों में ऐसे अन्य मामले, जिन्हें राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए राज्य की सरकार का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता दी गई है और वह महाराजा की उद्घोषणा के तहत उस समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है। मार्च, 1948 का पाँचवाँ दिन;

(सी) अनुच्छेद (1) और इस अनुच्छेद के प्रावधान उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(डी) इस संविधान के ऐसे अन्य प्रावधान उस राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश जो उप-खंड (बी) के पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट राज्य के विलय पत्र में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित है, राज्य सरकार के परामर्श के अलावा जारी नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हो, उस सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (बी) के पैराग्राफ (ii) में या उस खंड के उपखंड (डी) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट राज्य सरकार की सहमति दी जाए। राज्य के संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा बुलाई

गई है, इसे ऐसे निर्णय के लिए ऐसी सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले सकती है।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा जो वह निर्दिष्ट कर सकता है: बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। 26 जनवरी, 1950 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1950 बनाया गया था। 20 अप्रैल, 1951 को, जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने एक उद्घोषणा जारी की जिसके अनुसरण में 5 नवंबर, 1951 को जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा बुलाई गई। 10 जून, 1 022 1952 को जम्मू और कश्मीर संविधान की मूल सिद्धांत समिति सभा ने संविधान सभा को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि:-

(ए) जम्मू-कश्मीर के भावी संविधान का स्वरूप पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा,

(बी) वंशानुगत शासन की संस्था समाप्त कर दी जाएगी, और

(सी) राज्य के प्रमुख का कार्यालय वैकल्पिक होगा।

संविधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा इन सिफ़ारिशों को अपनाया। संकल्प का निम्नलिखित भाग प्रासंगिक है "अब, इसलिए, 12 जून, 1952 के संकल्प के अनुसरण में, और मसौदा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह विधानसभा निर्णय लेती है:

1. (i) कि राज्य का प्रमुख राज्य की विधान सभा की सिफारिशों पर संघ के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होगा;

(ii) वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहेगा;

(iii) वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना पद त्याग सकता है;

(iv) पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, राज्य का प्रमुख अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

बशर्ते कि वह, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता;

2. पैराग्राफ 1 के उप-पैरा (i) में निर्दिष्ट राज्य के प्रमुख की मान्यता के संबंध में राज्य की विधान सभा की सिफारिश चुनाव द्वारा की जाएगी;

4. कि राज्य के प्रमुख को सदर-ए-रियासत के रूप में नामित किया जाएगा।

15 नवंबर, 1952 को राष्ट्रपति ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए आदेश संख्या सीओ 44 जारी किया:

> "इस अनुच्छेद (कला. 370) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर, घोषणा की कि, 17 नवंबर, 1952 से, उक्त कला 370 इस संशोधन के साथ लागू होगा कि उसके खंड (1) में स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्: -"स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य की सरकार का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस समय जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता दी गई है, जो कार्य कर रहा है फिलहाल कार्यालय में रहने के लिए राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर।"

14 मई 1954 को सीएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। (1) कला का संविधान के 370, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 बनाया। इसने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1950 को हटा दिया। इसने भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को जम्मू

और कश्मीर राज्य पर लागू किया। कला के तहत 35, खंड (बी) के बाद निम्नलिखित खंड (सी) जोड़ा गया:

> "(सी) जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल द्वारा निवारक हिरासत के संबंध में बनाया गया कोई भी कानून, चाहे वह संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हो, जमीन पर शून्य नहीं होगा। कि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है, लेकिन ऐसा कोई भी कानून, ऐसी असंगतता की सीमा तक, उक्त आदेश के प्रारंभ से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद कर देगा, सिवाय किए गए कार्यों के संबंध में या उसकी समाप्ति से पहले किया जाना छोड़ दिया गया।"

हम दो अन्य एप्लिकेशन देख सकते हैं। कला के तहत 361, सीएल के बाद। (4) निम्नलिखित खंड जोड़ा गया, अर्थात्:

> "(5) इस अनुच्छेद के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे एक राजप्रमुख के संबंध में लागू होते हैं, लेकिन उस स्लेट के संविधान के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।"

1 024 कला के लिए। 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा गया, अर्थात्:

"(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है-

(ए) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भ को उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(बी) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों को उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले सदर-ए-रियासत के संदर्भों सहित माना जाएगा. "

कला के लिए 368 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया:

"बशर्ते कि ऐसा कोई भी संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 370 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू नहीं किया जाता है।"

हम इसका उल्लेख कर सकते हैं, जहां तक जम्मू राज्य का संबंध है। कश्मीर का संबंध था, संघ सूची में कुछ प्रविष्टियाँ संशोधित की गईं, प्रविष्टि 97 को हटा दिया गया, और राज्य सूची और समवर्ती सूची को छोड़ दिया गया।

17 नवंबर, 1956 को जम्मू-कश्मीर संविधान को अपनाया गया था। कुछ धाराएँ उस तिथि को लागू हुईं और शेष धाराएँ 26 जनवरी, 1957 को

लागू हुईं। 6 नवंबर, 1957 को कर्ण सिंह दूसरी बार सदर-ए-रियासत चुने गए। 31 अक्टूबर, 1962 को कर्ण सिंह तीसरी बार सदर-ए-रियासत चुने गये। 10 अप्रैल, 1965 को जम्मू और कश्मीर संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1965 को सदर-ए-रियासत की सहमति प्राप्त हुई। 24 नवंबर, 1965 को राष्ट्रपति ने कला के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। संविधान के 370, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 बनाया गया। इस आदेश के तहत, उप-सीएल के लिए। (बी) एल का (4) कला का 367 में निम्नलिखित खंड शामिल किए गए थे "(एए) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ में, सलाह पर कार्य करते हुए राज्य के मंत्रिपरिषद को उस समय के लिए जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

(बी) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भ को राज्यपाल के संदर्भ सहित माना जाएगा-

102 5 न ही जम्मू-कश्मीर का अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना;

बशर्ते कि 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में, ऐसे संदर्भों को उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले सदर-

ए-रियासत के संदर्भों सहित माना जाएगा। पार्टियों की स्थिति, और संविधान की धारा 370 में स्पष्टीकरण का महत्व है।

एटमी-जनरल के अनुसार यह उस समय प्रचलित संवैधानिक स्थितियों के अनुसार लेख के प्रयोजन के लिए डाली गई एक मात्र परिभाषा है। श्री गर्ग के अनुसार, यह भारत संघ और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच संपूर्ण संबंधों का मूलमंत्र है। उनके अनुसार न तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा और न ही राष्ट्रपति सदर-ए-रियासत के कामकाज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे और जहां तक जम्मू और कश्मीर के संविधान (छठे संशोधन) अधिनियम, 1965 ने सदर-ए-रियासत को प्रतिस्थापित किया था। राज्यपाल, यह अधिकारातीत है। उनके अनुसार, या तो कला के तहत भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। 369 और कला 370(3) या स्पष्टीकरण में संशोधन के लिए एक नई संविधान सभा बुलानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि संविधान का पाठ स्पष्ट है, तो उस पर प्रभाव डाला जाना चाहिए और संविधान में सुधार करना न्यायालयों का कर्तव्य नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं की थी।

यह हमें कला की अनिवार्य विशेषता प्रतीत होती है। 370, उप-खंड एल (बी) और (डी) के लिए राज्य सरकार की सहमति या राज्य सरकार के परामर्श की आवश्यकता है। किसी विशेष समय में राज्य सरकार क्या है,

इसका निर्धारण जम्मू-कश्मीर के संविधान के संदर्भ में किया जाना है। स्पष्टीकरण ने संवैधानिक स्थिति को मान्यता देने से अधिक कुछ नहीं किया, क्योंकि यह उस तिथि पर अस्तित्व में था और 17 नवंबर, 1952 से प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण ने भी राज्य में संवैधानिक स्थिति को मान्यता देने से अधिक कुछ नहीं किया।

इसलिए, हमें उस कला को धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है। 370(1)(बी) और कला। 370 (1) (डी) जम्मू और कश्मीर के संविधान के निर्माण या संशोधन पर कोई सीमा नहीं रखता। यदि कोई सीमा है तो उसे राज्य के संविधान में पाया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 147 में ही प्रावधान है कि उस धारा के तहत भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि कला को संशोधित करने का एकमात्र तरीका। 370 कला में निर्दिष्ट है। 370(3) ही उन्होंने कहा कि यह (1) [1969] 2 एससीआर 365 था।

इस न्यायालय द्वारा अभी संदर्भित निर्णय में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। हमें इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है कि कला.370(3) का उपयोग अब कला के प्रावधानों में संशोधन के लिए किया जा सकता है। 370(1) और (2), और इसलिए हम उस बिंदु पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। अब हमें कला में संशोधन से कोई सरोकार नहीं है। 370(1) हम

उस स्थिति से चिंतित हैं जहां स्पष्टीकरण काम करना बंद कर देता है। इसका संचालन बंद हो गया था क्योंकि अब जम्मू-कश्मीर का कोई सदर-ए-रियासत नहीं रहा। यदि स्पष्टीकरण में निहित परिभाषा "राज्य की सरकार" शब्दों पर लागू नहीं हो सकती है तो कला में दिया गया अर्थ। इसे संशोधित धारा 367(4) की जानकारी देनी होगी। यदि यह अर्थ दिया गया है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल कला में निर्धारित सहमति देने में सक्षम हैं। 370 और जम्मू-कश्मीर संविधान द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान एस की ओर आकर्षित किया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 147 उन्होंने कहा कि यह धारा भी सदर-ए-रियासत के शाश्वत अस्तित्व पर विचार करती है क्योंकि यह धारा स्पष्ट रूप से विधानसभा को कला के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने से रोकती है। 147 और इस धारा में निहित प्रावधानों में से एक यह है कि संविधान में संशोधन की सहमति सदर-ए-रियासत द्वारा दी जानी चाहिए। यह सच है कि एस.147 में प्रावधान है कि "इस संविधान में संशोधन केवल विधान सभा में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में कुल बहुमत के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है उस सदन की सदस्यता, इसे सदर-ए-रियासत के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और, विधेयक को ऐसी सहमति दिए जाने पर, संविधान

विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाएगा।" लेकिन संविधान में ही एस शामिल है। 158 जो प्रदान करता है कि "जब तक संदर्भ में अन्यथा सामान्य खंड अधिनियम, एस. 1977 की आवश्यकता न हो। इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा जैसा कि राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।" 'सामान्य खण्ड अधिनियम में धारा 18 शामिल है जिसमें लिखा है:

8. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाए गए किसी भी अधिनियम में, किसी भी पदाधिकारी के उत्तराधिकारियों या शाश्वत उत्तराधिकार वाले निगमों के साथ किसी कानून के संबंध को इंगित करने के उद्देश्य से, पदाधिकारियों या निगमों के साथ अपने संबंध को व्यक्त करना पर्याप्त होगा।।"

इस अधिनियम के आधार पर, यदि राज्यपाल सदरी-रिवासत का उत्तराधिकारी है। वह 'सदर-ए-रियासत' की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उत्तराधिकारी हैं.'मूल संविधान, एस द्वारा। 26, बशर्ते :

"26(1)। राज्य के प्रमुख को सदर-ए-रियासत के रूप में नामित किया जाएगा। (2) राज्य की कार्यकारी शक्ति सदर-ए-रियासत में निहित होगी और उसका प्रयोग सीधे तौर पर या उसके द्वारा किया जाएगा। इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से।

धारा 27 में सदर-ए-रियासत और 'सदर-ए-रियासत' के चुनाव का प्रावधान है। कार्यालय की अवधि के लिए 28 .इन प्रावधानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सदर-ए-रियासत वास्तव में राज्य के प्रमुख को दिया गया नाम है। राज्य संविधान में संशोधन के तहत राज्य को राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। उप-एस. धारा 26 का (2), यथासंशोधित, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उसमें निहित करता है।

यह सच है कि राज्यपाल को सदर-ए-रियासत की तरह निर्वाचित नहीं किया जाता है, लेकिन नियुक्ति का तरीका उन्हें सदर-ए-रियासत का उत्तराधिकारी तो नहीं बनाएगा। दोनों राज्य के मुखिया हैं.

श्री गर्ग ने तर्क दिया कि एस.एस. का संशोधन। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 26 और 27 ख़राब थी. अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य(1) में निम्नलिखित अनुच्छेद पर भरोसा किया:

> "अगला तर्क संविधान की धारा 368 में अभिव्यक्ति "संशोधन" पर आधारित है और यह तर्क दिया गया है कि उक्त अभिव्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक सामग्री है और संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके संसद इसकी संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। संविधान, लेकिन यह इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए केवल मूल उपकरण के

ढांचे के भीतर इसके प्रावधानों को संशोधित कर सकता है। यदि मूल तत्व विशेष बहुमत के साथ संशोधन की सामान्य प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे, तो तर्क आगे बढ़ता है, राष्ट्रपति की संस्था हो सकती है समाप्त किया जा सकता है, संसदीय कार्यपालिका को हटाया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, संघवाद की अवधारणा को समाप्त किया जा सकता है और संक्षेप में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को सरकार की अधिनायकवादी प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तर्क में काफी ताकत है।"

लेकिन मार्ग. उनके द्वारा उद्धृत संशोधन का शायद ही उनके द्वारा लाभ उठाया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए संशोधन, कला के स्पष्टीकरण की प्रकृति के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे संविधान की धारा 370, जम्मू-कश्मीर संविधान की रूपरेखा या बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं लाती है। 'मैं राज्य का राज्यपाल अभी भी मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्राप्त सरकार का प्रमुख बना हुआ हूं, और जो एकमात्र परिवर्तन हुआ है वह उसके पदनाम और मोड में है- (1) [1967] 2 एस.सीआर 762।

उनकी नियुक्ति के. ऐसा नहीं है कि इस तरह के बदलाव से राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के प्रति गैर-जिम्मेदार हो जाती है, या एक जिम्मेदार सरकार के रूप में उसका मौलिक चरित्र बदल जाता है। जिस प्रकार पहले सदर-ए-रियासत के कार्यालय की शुरुआत से उस सरकार के प्रमुख के पदनाम में परिवर्तन लाया गया था, उसी प्रकार उनके पदनाम में भी सदर-ए-रियासत से परिवर्तन लाया गया था। गर्वनर। सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल को नियुक्त किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया था। उस सरकार के चरित्र में लोकतांत्रिक से गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थामें इस तरह के बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। एक व्यापक तर्क, जो गोलकनाथ के मामले में उठाया गया था और जिसके संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणियाँ की गई थीं, हमारे सामने नहीं उठाया गया था, और इसलिए, वर्तमान में हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गर्ग ने हमारा ध्यान सीएलएस की ओर आकर्षित किया। (एए) और (बी) कला के। 367(4), 1965 के सीओ 74 द्वारा प्रतिस्थापित [संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) दूसरा संशोधन आदेश, 1965]। हम उन्हें पहले ही ऊपर बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कला में संशोधन है.370(1) पिछले दरवाजे से और राष्ट्रपति कला के तहत इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। 370(1) जब उसने कला के तहत इन शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा नहीं किया था। 370(3). लेकिन, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, स्पष्टीकरण निरर्थक हो गया था और

संविधान के अन्य भागों में सदर-ए-रियासत के संदर्भ भी निरर्थक हो गए थे। दो विकल्प थे; सबसे पहले, या तो राज्य सरकार शब्द की व्याख्या करने और इसका कानूनी अर्थ देने के लिए अदालतों को छोड़ दिया जाए, या दूसरा, सेंट परिभाषा खंड में कानूनी अर्थ दिया जाए। जो किया गया है वह सीएलएस (एए) और जोड़कर किया गया है। (बी) एक परिभाषा प्रदान की गई है जो किसी भी स्थिति में न्यायालयों के पास होगी। इसलिए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पिछले दरवाजे से कला 370(1) में कोई संशोधन किया गया है।

यदि हमने इसे कला में संशोधन के रूप में माना होता। 370(1), तो हमें इस पर विचार करना होगा कि संशोधनात्मक शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग किया गया था या नहीं, लेकिन जैसा कि हमने कहा है, हमें इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है।

निष्कर्ष में हम मानते हैं कि संशोधन अधिनियम को राज्यपाल द्वारा वैध रूप से सहमति दी गई थी।

श्री गर्ग द्वारा आग्रह किए गए दूसरे बिंदु पर आते हुए, हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1967 किसी को भी कोई विधायी शक्तियाँ कैसे सौंपता है, यह प्रावधान को सम्मिलित करके हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। धारा 8 यह निर्देशित

करने के लिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाए कि उसे उन आधारों के बारे में सूचित करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा जिनके आधार पर एम. एम. डैमनू बनाम. जे. एंड के, स्टेट (सीकरी, सी. जे.) नजरबंदी का आदेश दिया गया था। जब बंदी प्राधिकारी ऐसा निर्देश देने का विकल्प चुनता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बंदी प्राधिकारी किसी विधायी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के विभिन्न प्राधिकरणों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है जहां प्रत्यायोजन या विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के प्रश्न पर विचार किया गया है।

यह भी आवश्यक नहीं है कि तीसरे बिंदु पर ध्यान दिया जाए, अर्थात्, कला का उल्लंघन। 21 और संविधान का 22 क्योंकि यह है स्पष्ट करें कि वे कला द्वारा बहिष्कृत हैं। 35 ((c) संविधान का। यह सुझाव दिया गया था कि एस। 75 (1) दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन किया गया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एस। 75 (1) स्पष्ट रूप से अनुपालन किया गया है क्योंकि निरोध आदेश लेखन में है और निरोध प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। एस को संदर्भ दिया गया था। 76, क्र. पी. सी., लेकिन इस प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह केवल तभी लागू होता है जब न्यायालय निर्देश देता है कि सुरक्षा ली जाए। चौथा बिंदु यह है कि एस के लिए परंतुक। 8 जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित,1967 खराब है क्योंकि यह

एस के साथ संघर्ष में है। 103 जम्मू और कश्मीर का संविधान। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका ने एस को सीधे संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। 103, और न ही उसे उच्च न्यायालय द्वारा एस के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति है। 103 भ्रमपूर्ण। (प्रेम चंद गर्ग बनाम देखें। आबकारी आयुक्त, यू. पी. (1), जहाँ इस न्यायालय ने आर. 12, ओ. XXXV उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर फैसला सुनाया कि उसने कला के तहत मौलिक अधिकारों के दावे या विंडी कैशन को धीमा कर दिया। 32.) श्री गर्ग ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए अदालत को संतुष्ट करना असंभव था कि उसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसे हिरासत में लिए जाने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और उसे यह बताना कि उसे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था, उसे कुछ भी नहीं बताना है, और यह हो सकता है कि जिस वास्तविक आधार पर उसे हिरासत में लिया गया था, उसका राज्य की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। श्री गर्ग के तर्क में कुछ ताकत है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हम यह मानने में असमर्थ हैं कि यह परंतुक अधिकार से बाहर है क्योंकि परंतुक और अधिनियम उच्च न्यायालय या इस न्यायालय को इससे नहीं रोकते हैं नजरबंदी की वैधता को देखना। इसे याद रखना चाहिए।

ए.के.गोपालन बनाम. मद्रास राज्य (1) एस। 14 में से निवारक निरोध अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। कनिया, सी. जे. पृष्ठ 130 पर इस बिंदु पर देखा गयाः

"उस धारा द्वारा न्यायालय को रोका जाता है (सिवाय इसके कि - इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सजा का उद्देश्य) से एक बयान द्वारा या नेतृत्व द्वारा सूचित किया जा रहा है साक्ष्य, व्यक्त किए गए आधारों के सार का धारा 7 के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति जिस पर आदेश किया गया था, या उसके द्वारा किया गया कोई प्रतिनिधित्व

इस तरह के आदेश के खिलाफ। यह न्यायालय को भी रोकता है किसी भी लोक अधिकारी से पदार्थ का खुलासा करने के लिए कहना उन आधारों से या कार्यवाही के उत्पादन से सलाहकार मंडल की रिपोर्ट जो हो सकती है - गोपनीय घोषित किया गया। यह स्पष्ट है कि यदि यह प्रावधान अदालत को खड़े होने की अनुमति है कोई सामग्री नहीं हो सकती है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हिरासत उचित है या नहीं। मेरा मतलब यह नहीं है कि क्या आधार पर्याप्त हैं। ज्ञान है या नहीं। यह न्यायालय को यह पता लगाने से भी रोकता है कि यह पता लगाना कि क्या हिरासत के कथित आधार हैं परिस्थितियों या वर्ग से संबंधित कुछ भी या धारा 12 (1) (क) में उल्लिखित मामलों के वर्ग या (ख) "। लेकिन सौभाग्य से इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यह उच्च न्यायालय और

सर्वोच्च न्यायालय को उचित मामलों में राज्य को उसके समक्ष निरोध के आधार और अन्य सामग्री पेश करने का आह्वान करके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है ताकि खुद को संतुष्ट किया जा सके कि बंदी को हिरासत में लिया जा रहा था

कानून के अनुसार। यदि ऐसा नहीं होता, तो हमें परंतुक को बनाए रखने में कठिनाई होती। हमने राज्य द्वारा हमारे सामने पेश की गई फाइल को देखा है और हम संतुष्ट हैं कि जिन आधारों पर बंदी को हिरासत में लिया गया है, वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। और इसके साथ श्री गर्ग द्वारा उठाया गया पाँचवाँ बिंदु भी विफल हो जाता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया था मामला।

परिणामस्वरूप याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरि वल्लभ खत्री (आर०जे०एस०) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।